

उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग के विकास में सरकारी प्रयासों की प्रासंगिकता एक :**समीक्षात्मक अध्ययन*****डॉ॰ अज़हरुद्दीन**

सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, एम.एल.के.पी.जी. कॉलेज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश

Article Received: 13 August 2026

***Corresponding Author: डॉ॰ अज़हरुद्दीन**

Article Revised: 03 September 2026

सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, एम.एल.के.पी.जी. कॉलेज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश

Published on: 23 September 2026

DOI: <https://doi-doi.org/101555/ijrpa.4882>**सारांश**

उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि पर बढ़ते दबाव, छोटी एवं सीमांत जोतों की अधिकता, ग्रामीण बेरोजगारी तथा किसानों की आय में विविधीकरण की आवश्यकता के कारण डेयरी फार्मिंग को आजीविका के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2024-25 में देश के कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 15.66 प्रतिशत रही और राज्य देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना रहा। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना तथा विभिन्न प्रसंस्करण एवं अवसंरचना संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत समीक्षा में इन सरकारी प्रयासों की प्रासंगिकता, उपलब्धियों, सीमाओं तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख शब्द: डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध सहकारी समितियाँ, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

1. प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन कृषि का पूरक व्यवसाय होने के साथ-साथ लाखों परिवारों के लिए नियमित आय का स्रोत है। विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें छोटे एवं सीमांत किसान, भूमिहीन परिवार तथा ग्रामीण महिलाएँ भी अपेक्षाकृत कम भूमि के साथ भागीदारी कर सकती हैं। दूध की नियमित बिक्री किसान को दैनिक अथवा साप्ताहिक नकदी प्रवाह उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि आय में स्थिरता आती है।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में डेयरी क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 15.66 प्रतिशत था और राज्य प्रथम स्थान पर रहा। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में लगभग 86 प्रतिशत किसान भूमिहीन या 0-1 हेक्टेयर की छोटी जोत वाले हैं तथा प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14 प्रतिशत मध्य उत्तर प्रदेश, 31 प्रतिशत पूर्वी उत्तर प्रदेश और 5 प्रतिशत बुंदेलखंड से प्राप्त होता है।

इसलिए डेयरी फार्मिंग केवल दूध उत्पादन का विषय नहीं है, बल्कि यह **ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तीकरण, पोषण सुरक्षा, किसान आय, सहकारिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण** से जुड़ा हुआ क्षेत्र है।

2. उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग की वर्तमान स्थिति

उत्तर प्रदेश की विशाल ग्रामीण आबादी, पशुधन की उपलब्धता और दूध की बड़ी उपभोक्ता मांग डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। राज्य में भैंस तथा गाय दोनों दुग्ध उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। राज्य सरकार के निवेश संबंधी आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध देने वाली भैंसों की संख्या तथा भैंस के दूध उत्पादन में देश में अग्रणी है, जबकि दुग्ध देने वाली गायों की संख्या भी अत्यधिक है।

फिर भी उत्पादन की अधिकता अपने-आप में डेयरी क्षेत्र के पूर्ण विकास का संकेत नहीं है। उत्पादन के साथ-साथ **दूध का संग्रहण, शीतलीकरण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक पहुँच** भी आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की डेयरी नीति के अनुसार नीति के निर्माण के समय राज्य में संगठित क्षेत्र द्वारा केवल लगभग 10 प्रतिशत बाजार योग्य अधिशेष दूध का प्रसंस्करण किया जा रहा था, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 17 प्रतिशत था। अतः राज्य के सामने मुख्य चुनौती केवल अधिक दूध पैदा करना नहीं, बल्कि **दूध को लाभकारी आर्थिक उत्पाद में बदलना** है।

3. डेयरी फार्मिंग के विकास हेतु प्रमुख सरकारी प्रयास

3.1 उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022

उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी क्षेत्र को उत्पादन से आगे बढ़ाकर प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के उद्देश्य से **उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022** लागू की। नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य में दुग्ध आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना, दुग्ध उत्पादकों को बाजार आधारित लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना तथा दूध के प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाना है। नीति में अगले पाँच वर्षों में

₹5,000 करोड़ के पूंजी निवेश का लक्ष्य तथा दूध प्रसंस्करण स्तर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

नीति के अंतर्गत डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सहायता, पशु आहार इकाइयों को प्रोत्साहन, कोल्ड-चेन, मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पाद तथा तकनीकी उन्नयन जैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं। उदाहरणतः पात्र नई या विस्तारित दूध प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी आदि की लागत पर 10 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹5 करोड़ की पूंजीगत सहायता का प्रावधान है।

प्रासंगिकता

यह नीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे डेयरी क्षेत्र को **कच्चे दूध के उत्पादन से संगठित डेयरी उद्योग** की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। इससे रोजगार, मूल्य संवर्धन, निर्यात और किसानों के लिए बाजार के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

3.2 नन्द बाबा दुग्ध मिशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने तथा दूध उत्पादकों को स्थानीय स्तर पर उचित बाजार उपलब्ध कराने के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक गाँव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से दूध उत्पादकों को गाँव में ही उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है।

मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना तथा मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना जैसी योजनाएँ संचालित हैं।

प्रासंगिकता

नन्द बाबा दुग्ध मिशन की विशेष प्रासंगिकता इस बात में है कि यह **उत्पादन, सहकारिता और बाजार** को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। छोटे किसानों के लिए स्थानीय दुग्ध सहकारी समिति दूध बेचने का अपेक्षाकृत सुरक्षित माध्यम बन सकती है।

3.3 नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना

डेयरी फार्मिंग के व्यावसायीकरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं की उपलब्धता आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक डेयरी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया

जानकारी के अनुसार इस योजना में डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए **50 प्रतिशत तक सब्सिडी** का प्रावधान किया गया है।

प्रासंगिकता

इस प्रकार की सहायता से किसान पारंपरिक पशुपालन से आगे बढ़कर **व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग** की ओर बढ़ सकते हैं। इससे नस्ल सुधार, दूध उत्पादन तथा पशुपालक परिवारों की आय में वृद्धि की संभावना रहती है।

3.4 नस्ल सुधार एवं पशुपालक प्रोत्साहन

डेयरी विकास में पशुओं की नस्ल, स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रजनन क्षमता महत्वपूर्ण कारक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पशुधन को प्रोत्साहित करना और बेहतर पशुपालन को आर्थिक प्रोत्साहन देना है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा स्वच्छ दूध उत्पादन तथा नस्ल सुधार के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नीति में शामिल की गई है।

3.5 दूध प्रसंस्करण एवं कोल्ड-चेन का विकास

दूध शीघ्र खराब होने वाला उत्पाद है। इसलिए दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ **Bulk Milk Cooler, chilling centres, refrigerated vehicles और अन्य cold-chain infrastructure** का विकास अत्यंत आवश्यक है।

दुग्ध नीति-2022 में कोल्ड चैन की स्थापना तथा Bulk Milk Cooler आदि के लिए ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है।

यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की बर्बादी कम करने, गुणवत्ता बनाए रखने तथा किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

3.6 मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा

दूध को केवल तरल दूध के रूप में बेचने की अपेक्षा उससे **पनीर, घी, दही, मक्खन, आइसक्रीम, दूध पाउडर और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद** तैयार करने से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

दुग्ध नीति-2022 में मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों की इकाइयों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय उद्यमिता तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास की संभावना बढ़ती है।

4. सरकारी प्रयासों की प्रासंगिकता का विश्लेषण

4.1 किसान आय में वृद्धि

डेयरी किसानों को कृषि के साथ नियमित आय उपलब्ध कराती है। यदि किसान को उचित मूल्य, बेहतर नस्ल, पशु स्वास्थ्य सेवाएँ, सस्ता चारा और संगठित बाजार उपलब्ध हो, तो डेयरी उसकी आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

4.2 ग्रामीण रोजगार

डेयरी फार्मिंग पशुपालन तक सीमित नहीं है। इसके साथ पशु आहार, दूध संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और मूल्यवर्धित उत्पादों से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अतः सरकारी निवेश का रोजगार गुणक प्रभाव हो सकता है।

4.3 महिला सशक्तीकरण

ग्रामीण परिवारों में पशुपालन एवं दूध उत्पादन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा महिला डेयरी उद्यमियों को अधिक संस्थागत सहायता मिले तो डेयरी फार्मिंग महिला आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

4.4 ग्रामीण औद्योगिकीकरण

दुग्ध नीति-2022 का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें केवल पशुपालक ही नहीं, बल्कि **processing units, cattle feed units, cold chain और value-added products** को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इससे गाँवों और छोटे कस्बों में कृषि-आधारित उद्योगों के विकास को गति मिल सकती है।

4.5 पोषण सुरक्षा

दूध प्रोटीन, कैल्शियम तथा अन्य पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का संबंध केवल किसान आय से नहीं, बल्कि राज्य की पोषण सुरक्षा से भी है।

5. सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रमुख चुनौतियाँ

सरकारी योजनाओं की व्यापकता के बावजूद उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र के सामने कई संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं।

पहली चुनौती—छोटे पशुपालकों की स्थिति। बड़ी संख्या में किसान छोटी जोत या भूमिहीन श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके लिए आधुनिक डेयरी तकनीक में निवेश करना कठिन हो सकता है।

दूसरी चुनौती—चारे की उपलब्धता एवं लागत। संतुलित पशु आहार की लागत बढ़ने से डेयरी की लाभप्रदता प्रभावित होती है।

तीसरी चुनौती—पशु स्वास्थ्य। रोग नियंत्रण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा समय पर पशु चिकित्सा सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

चौथी चुनौती—प्रसंस्करण का निम्न स्तर। राज्य में दूध उत्पादन बहुत अधिक होने के बावजूद प्रसंस्करण क्षमता में अभी पर्याप्त विस्तार की आवश्यकता है। स्वयं राज्य की नीति ने भी इस अंतर को रेखांकित किया है।

पाँचवीं चुनौती—बाजार एवं मूल्य। छोटे उत्पादकों को कई बार संगठित बाजार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और मूल्यवर्धन की सुविधाएँ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पातीं।

छठी चुनौती—योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्या। किसी भी सरकारी योजना की वास्तविक सफलता उसके बजट से अधिक उसके जमीनी क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पहचान, समय पर सब्सिडी, प्रशिक्षण और निगरानी पर निर्भर करती है।

6. भविष्य के लिए सुझाव

उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी हो सकते हैं—

1. **ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रह एवं Bulk Milk Cooler की संख्या बढ़ाई जाए।**
2. छोटे पशुपालकों को FPO तथा दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ा जाए।
3. महिला स्वयं सहायता समूहों को डेयरी उद्यमिता से जोड़ा जाए।
4. गुणवत्तापूर्ण चारा और पशु आहार की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. पशु चिकित्सा, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को ग्राम स्तर तक मजबूत किया जाए।
6. दूध की गुणवत्ता जाँच और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सार्वभौमिक बनाया जाए।
7. पनीर, घी, दही, मक्खन आदि मूल्यवर्धित उत्पादों के छोटे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
8. पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड जैसे अपेक्षाकृत कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में विशेष डेयरी क्लस्टर विकसित किए जाएँ।
9. जलवायु-स्मार्ट एवं कम लागत वाली डेयरी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए।
10. सरकारी योजनाओं के परिणामों का **जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियमित सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यांकन** किया जाए।

7. भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति

जैसा की हम सभी जानते हैं भारत में कृषि के साथ-साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग ऐसी गतिविधि है जिससे किसानों को नियमित नकद आय

प्राप्त होती है। फसल उत्पादन के विपरीत दुग्ध उत्पादन से दैनिक अथवा नियमित आय की संभावना रहती है। इसलिए लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन परिवारों तथा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि, विशाल ग्रामीण जनसंख्या, पशुधन संसाधन तथा दुग्ध की बड़ी उपभोक्ता मांग के कारण डेयरी फार्मिंग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा भी दुग्ध उत्पादन को केवल पशुपालन की गतिविधि न मानकर ग्रामीण रोजगार, आय वृद्धि, महिला सहभागिता तथा कृषि-आधारित उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 2023-24 में देश के कुल 239.30 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16.21 प्रतिशत थी। राजस्थान 14.51 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश 8.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ इसके बाद रहे।

तालिका 1 : भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति

सूचक	वर्ष 2023-24
भारत का कुल दुग्ध उत्पादन	239.30 मिलियन टन
भारत के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी	16.21%
उत्तर प्रदेश की स्थिति	प्रथम
राजस्थान की हिस्सेदारी	14.51%
मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी	8.91%
गुजरात की हिस्सेदारी	7.65%
महाराष्ट्र की हिस्सेदारी	6.71%

स्रोत: Department of Animal Husbandry & Dairying, *Basic Animal Husbandry Statistics 2024*.

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का डेयरी क्षेत्र राष्ट्रीय दुग्ध अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

8. निष्कर्ष

समग्र रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग के विकास के लिए सरकारी प्रयास **अत्यंत प्रासंगिक और समयानुकूल** हैं। राज्य पहले से ही देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 15.66 प्रतिशत रही। इसलिए वर्तमान चुनौती उत्पादन

की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ उसकी **गुणवत्ता, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बाजार एवं किसान की वास्तविक आय** बढ़ाने की है।

दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 ने निवेश, प्रसंस्करण, कोल्ड-चेन और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए एक व्यापक ढाँचा उपलब्ध कराया है। वहीं नन्द बाबा दुग्ध मिशन तथा उससे संबद्ध योजनाएँ पशुपालकों, दुग्ध सहकारिता और ग्रामीण स्तर पर दूध के विपणन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

अतः कहा जा सकता है कि **उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग का अगला चरण “अधिक दूध उत्पादन” से आगे बढ़कर “अधिक उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता, अधिक प्रसंस्करण और अधिक किसान आय” का होना चाहिए।** यदि सरकारी योजनाओं का लाभ छोटे एवं सीमांत पशुपालकों तक पारदर्शी रूप से पहुँचता है और उत्पादन को प्रसंस्करण तथा बाजार से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाता है, तो डेयरी फार्मिंग उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तीकरण, किसान आय और समावेशी ग्रामीण विकास का अत्यंत प्रभावी माध्यम बन सकती है।

संदर्भ-सूची

1. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार. *Basic Animal Husbandry Statistics 2025*.
2. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार. *Annual Report 2025–26*.
3. उत्तर प्रदेश सरकार, Invest UP. *Uttar Pradesh Dairy Development and Milk Products Promotion Policy–2022*.
4. उत्तर प्रदेश सरकार, Invest UP. *Dairy Sector—Uttar Pradesh*.
5. दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश. *नन्द बाबा दुग्ध मिशन*.
6. उत्तर प्रदेश सरकार. *नन्द बाबा दुग्ध मिशन—योजनाओं के शासनादेश*.